

## लेटरल एंट्री योजना से संबंधित चुनौतियाँ

### प्रलिमिन्स के लिये:

लेटरल एंट्री स्कीम (LES), संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), अन्य पछिड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), नीति आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC)।

### मेन्स के लिये:

नौकरशाही में लेटरल एंट्री का मुद्दा, इसके नहितार्थ और आगे की राह।

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

## चर्चा में क्यों?

नजी क्षेत्र के पेशेवरों को अनुबंध पर वरिष्ठ नौकरशाही में शामिल होने में सक्षम बनाने वाली लेटरल एंट्री योजना (LES), वधिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से विवाद का मुद्दा बनी हुई है।

- इसके तहत वर्ष 2019 से अब तक 63 नयुक्तियाँ की जा चुकी हैं लेकिन वैधानिक ढाँचे की कमी और हाशिये पर स्थिति समुदायों के आरक्षण को लेकर चर्चा बनी हुई है।

**नोट:** इससे संबंधित कानूनी विवाद फरवरी 2020 में शुरू हुआ जब IFS अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने वधिक एवं प्रक्रियात्मक जटिलता का हवाला देते हुए नैनीताल केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) के समक्ष लेटरल एंट्री स्कीम को चुनौती दी।

## लेटरल एंट्री योजना से संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं?

- संवैधानिक वैधता:** इसे संविधान के अनुच्छेद 309 के साथ वरिष्ठाभासी बताते हुए चुनौती दी गई थी, जो उपयुक्त वधायिका (संसद, राज्य वधायिका) को लोक सेवकों की भर्ती और सेवा की शर्तों को वनियमित करने वाले कानून बनाने का अधिकार देता है।
  - इसके अलावा, भर्ती में आरक्षण को समाप्त करना सामाजिक न्याय और संवैधानिक आदेशों को कमजोर करता है।
- लघु कार्यकाल:** लेटरल एंट्री के लिये 3 वर्ष का कार्यकाल प्रभावी शासन अनुकूलन और जवाबदेही के लिये बहुत छोटा माना जाता है।
- आनंद का सिद्धांत और सामूहिक भर्ती:** सरकार अनुच्छेद 310 के तहत LES को उचित ठहराती है, जो राष्ट्रपति को विशेषज्ञों की नयुक्ति करने की अनुमति देता है। आलोचकों का तर्क है कि यह वरिष्ठ, अस्थायी पदों पर बड़े पैमाने पर भर्ती के लिये नहीं है।
  - अधिकारियों की कमी का हवाला देते हुए, इसकी आवश्यकता पर सवाल उठाया गया है, क्योंकि प्रत्येक रक्ति के लिये 18 पैलबद्ध अधिकारी हैं।
- हितों का टकराव:** चर्चाओं में नजी क्षेत्र के पेशेवरों द्वारा सरकारी नीतियों को प्रभावित करने की संभावित पूर्वाग्रहता तथा पृष्ठभूमि जाँच और सतर्कता मंजूरी जैसी सख्त जाँच का अभाव शामिल है।
- नौकरशाही मनोबल संबंधी चर्चाएँ:** लेटरल एंट्री की संख्या में वृद्धि से व्यावसायिक नौकरशाहों के मनोबल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वे लेटरल एंट्री का वरिष्ठ कर सकते हैं, उन्हें बाहरी व्यक्तियों के रूप में देख सकते हैं और पदानुक्रम और व्यवधान की चर्चाओं के कारण संभावित रूप से शत्रुता को बढ़ावा दे सकते हैं।

## लेटरल एंट्री स्कीम (LES) से संबंधित मुख्य बटु क्या हैं?

- LES: वर्ष 2018 में शुरू की गई LES एक भर्ती प्रक्रिया है जो नजी क्षेत्र के पेशेवरों को सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं को दरकिनार करते हुए सीधे मध्य-स्तर या वरिष्ठ सरकारी पदों पर नयुक्त करने की अनुमति प्रदान करती है।

- उन्हें संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा 3 वर्ष के अनुबंध पर नियुक्त किया जाता है, जिसकी अवधि अधिकतम 5 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।
- आरक्षण प्रावधान: लेटरल एंट्री को "एकल पद" माना जाता है, इसलिये इन्हें SC, ST, OBC और EWS श्रेणियों के लिये आरक्षण प्रणाली के कोटा के अधीन नहीं रखा गया है।
- भर्ती: वर्ष 2018 से अब तक 63 लेटरल प्रवेशकों की नियुक्ति की गई है, जिनमें से 57 अगस्त, 2023 तक सेवारत होंगे।
  - आरक्षण अधिकारियों को लेकर प्रतारोध के कारण, UPSC ने अगस्त, 2024 में LEC के तहत 45 वर्षिष्ठ पदों पर भर्ती रोक दी।

## सविलि सेवाओं में लेटरल एंट्री के क्या लाभ हैं?

- वशिषिट वशिषज्जता: लेटरल एंट्री प्रौद्योगिकी, प्रबंधन और वतित जैसे क्षेत्रों में वशिषज्जों की भर्ती को सक्षम बनाता है, जिससे ज्ज्ञान संबंधी अंतराल को संबोधित किया जाता है, जिसकी पूरत सामान्य सविलि सेवक द्वारा नहीं की जा सकती है।
- कुशल संचालन: लेटरल एंट्री से लगभग 1500 IAS अधिकारियों की कमी को दूर करने और सरकारी एजेंसियों के कुशल संचालन में मदद मलि सकती है।
- कार्य संस्कृत में सुधार: पारश्व प्रवेशकर्त्ता लालफीताशाही से दूर होकर अधिकि गतशील, परणाम-उनमुख शासन की ओर बदलाव को बढ़ावा देते हुए नौकरशाही नष्किरयिता में सुधार लाने में मदद कर सकते हैं।
- समावेशी शासन: पारश्व प्रवेश से नज्जी क्षेत्र और गैर-लाभकारी संस्थाओं सहति हतिधारकों की अधिकि भागीदारी संभव होती है, जिससे सहभागी शासन और बहु-अभनिता सहयोग में वृद्धि होती है।

## आगे की राह

- दोहरी प्रवेश प्रणाली: भारतीय रजिर्व बैंक के पूरव गवरनर डी. सुबबाराव ने एक दोहरी प्रवेश प्रणाली का सुझाव दिया था, जिसमें 25 से 30 वर्षीय आयु वर्ग के लिये परंपरागत भर्ती तथा संबद्ध क्षेत्र के वशिषज्जों की नियुक्ति किये जाने के उद्देश्य से 37 से 42 वर्षीय आयु वर्ग के लिये मध्य-करयिर पारश्व प्रवेश की व्यवस्था थी।
  - युवा, गतशील प्रतभि युक्त व्यक्तियों को आकर्षति करने हेतु संयुक्त सचवि पदों के लिये आयु सीमा में छूट दिये जाने का सुझाव दिया गया था।
- पारश्व प्रवेशकर्त्ताओं के लिये प्रशक्षण: नज्जी क्षेत्र से सरकारी भूमिकाओं में पारश्व प्रवेशकर्त्ताओं के संक्रमण को सरल बनाने के उद्देश्य से व्यापक प्रशक्षण प्रदान करने हेतु समरपति प्रशासनकि वशिषवदियालय की स्थापना की जानी चाहिये।
- नज्जी क्षेत्र का अनुभव: IAS और IPS अधिकारियों को नज्जी क्षेत्र में अनुभव प्राप्त करने की अनुमति देने से शासन में प्रतसिपर्द्धा, नवाचार और क्षेत्रीय वशिषज्जता बढ़ सकती है।

?????? ???? ?????:

प्रश्न. सरकार की लोक सेवाओं में लेटरल एंट्री की योजना क्या है? इसके गुणागुण और नहितार्थ क्या हैं?

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. "आरथकि प्रदर्शन के लिये संस्थागत गुणवत्ता एक नरिणायक चालक है"। इस संदर्भ में लोकतंत्र को सुदृढ करने के लिये सविलि सेवा में सुधारों के सुझाव दीजिये। (2020)